# डॉक्टरों व कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व निकम्मापन

**फ़रीदाबाद (म.मो.)** बीमाकृत मज़दूर प्रायः शिकायत करते हैं कि ईएसआई के डॉक्टर पैसा ले कर मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनाते हैं, ड्यूटी से गैरहाज़िर रहते हैं, हाज़िर हों तो भी मरीज़ों को देखने की बजाय गपोष्ठी में व्यस्त रहते हैं। दवाइयां बेचने तक के मामले प्रकाश में आये हैं। अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा भी दुर्व्यवहार की शिकायतें भी देखने-सुनने में आती हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी होती हैं। अक्सर प्रयोगशाला में देखने को मिलता है कि मरीज़ सैंपल देने 12 बजे पहुंचा तो कर्मचारी कहते हैं कि समय तो समाप्त हो गया, कल आना। मरीज कहता है कि वह दिहाड़ी तोड़ कर, किराया-भाड़ा खर्च कर के इतनी दूर आया और कल फ़िर आये, यह तो सरासर बेइंसाफ़ी है। इसके लिए वह कर्मचारियों और डॉक्टरों से उलझ पड़ता है। यहां कर्मचारी अपनी जगह सही है और मरीज़ अपनी जगह। ग़लत है तो वही प्रशासन, सरकार की वह नीतियां जो मरीज़ को नज़र नहीं आतीं, जिनके तहत 10 कर्मचारियों की जगह केवल चार से काम लिया जा रहा है। यदि पूरे कर्मचारी हों तो प्रयोगशाला को 24 घंटे भी चलाया जा सकता है जिससे मरीज़ कभी भी सैंपल दे सकता है। इसी तरह एक्स-रे विभाग में भी हर समय एक्स-रे कराया जा सकता है।

रही बात डॉक्टरों की रिश्वतखोरी और गैरहाज़िरी की, तो इसके लिए भी सरकार व उच्चाधिकारी ही पूरी तरह से दोषी हैं। यदि सरकार व इसके उच्चाधिकारी चाहें तो डॉक्टर की क्या मजाल जो गैर हाज़िर तो दूर की बात 2 मिनट लेट भी हो जाएं। पिछले दिनों श्रम विभाग के तत्कालीन श्रम सचिव राजकुमार के बेटे का दिल्ली स्थित उनके आवास पर विवाह समारोह था तो यहां के तीन डॉक्टर वहां वेटरों की तरह सेवा में जुटे थे। इसी तरह पूर्व डॉयरेक्टर सहारण ने भी कुछ पप्पू पाल रखे थे, जिनकी ड्यूटी सिर्फ़ उसकी कार बेगार करना मात्र थी। ऐसे लोगों के लिए गैरहाजिर होना तथा रिश्वतखोरी, दवाएं आदि बेच खाना सब कुछ जायज़ है क्योंकि ये लोग लूट में से ऊपर तक 'सेवा पानी' पहुंचाते हैं। अस्पताल में फ़ार्मासिस्टों की 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जिन्हें 'सेवा पानी' के आधार पर स्वयं श्रममंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था। जानकारों के अनुसार सहारण ने मंत्री को सुझाव दिया कि तीन लोगों से 'सेवा पानी' की बजाए यह सारा काम उन्हें अकेले ही करने दो तो इससे उसकी 'सेवा पानी' तो बेहतर होगी ही, बात भी ज्यादा लोगों तक नहीं फैलेगी।

ईएसआई अस्पताल के हर काऊंटर पर मरीजों की भारी भीड़ नज़र आती है। जिन मरीज़ों को आराम की जरूरत होती है वे लाइनों में खड़े अपनी बारी के इंतज़ार में जूझ रहे होते हैं, जो इंतज़ार एवं मशक्कत अच्छे भले इंसान को थका देती है उसे झेलने को ये मरीज़ मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की कुनीतियों व कुप्रबंधन के चलते न तो डिस्पेंसरियों का नेटवर्क मजबूत किया गया है और न ही ईएसआई के अनुसार स्टॉफ़ रखा गया है। कहने की जरूरत नहीं जब एक या दो चार लोग ऊपरी आशीर्वाद से किसी संस्थान में रिश्वतखोरी व हरामखोरी करते हैं तो बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा एवं उत्साह प्राप्त होता है। इसके चलते यह छूत की बीमारी की तरह सारे स्टाफ़ में फ़ैलने लगती है, जिससे कोई बिरले, जुझारू एवं ईमानदार लोग ही बच पाते हैं।

> "ईएसआई अस्पताल के हर काऊंटर पर मरीजों की भारी भीड़ नज़र आती है। जिन मरीज़ों को आराम की जरूरत होती है वे लाइनों में खड़े अपनी बारी के इंतज़ार में जूझ रहे होते हैं, जो इंतज़ार एवं मशक्कत अच्छे भले इंसान को थका देती है उसे झेलने को ये मरीज़ मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की कुनीतियों व कुप्रबंधन के चलते न तो डिस्पेंसरियों का नेटवर्क मजबूत किया गया है और न ही ईएसआई के अनुसार स्टॉफ़ रखा गया है। कहने की जरूरत नहीं जब एक या दो चार लोग ऊपरी आशीर्वाद से किसी संस्थान में रिश्वतखोरी व हरामखोरी करते हैं तो बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा एवं उत्साह प्राप्त होता है।"

# मंत्री जी का औचक छापा

**पानीपत (म.मो.)** राजस्व मंत्री शिवचरण शर्मा ने पानीपत में तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान भारी अनियमिततायें पकड़ीं। उनके छापे के दौरान काफ़ी संख्या में तहसील में अपना काम कराने आये लोगों ने शिकायतों के ढेर लगा दिये। पार्षद हरीश शर्मा ने तहसील में होने वाली अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा ही खोल कर रख दिया। सभी लोगों का कहना था कि बिना सुविधा शुल्क दिये यहां कोई काम नहीं होता।

सभी जानते हैं कि तहसील कार्यालय ऐसा कार्यालय है जहां पैसों की बरसात होती है।

मंत्री जी शिवचरण शर्मा पहले कोलोनाइजर रह चुके हैं, इसलिए इन्हें तहसीलों की कार्य प्रणाली का अच्छा ज्ञान है। इन्हें यह भी पता है कि तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार लगने के लिए ऊपर तक कितना चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है।

वैसे मंत्री जी ने तहसील कार्यालय पर छापा मार कर अच्छा काम किया है, पर क्या इससे तहसीलदार भयभीत हो कर घास चरने लगेंगे?

मंत्री जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी दो तहसीलें हैं - फरीदाबाद तहसील और बल्लबगढ़ तहसील। वहां भी लूट-खसूट का धंधा पूरे जोरों पर चलता है। कोई भी चढ़ावा चढ़ाये बिना निकल नहीं सकता। क्या यहां भी मंत्री जी छापे मारेंगे? दोषी अपराधियों को पकड़ेंगे? उन्हें अगर आज पकड़ लिया तो कल छूट भी जायेंगे और फ़िर लूटने के काम में लग जायेंगे।

जब प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट हो तो मंत्री जी कहां-कहां छापे मारेंगे और इससे होगा क्या? होगा तो तब जबकि इस छापेमारी से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में यह संदेश पहुंचे कि वे किसी भी स्तर पर बख्शे नहीं जायेंगे और लूट-खसूट करते पकड़े गये तो कहीं के नहीं रहेंगे। तहसीलदारों द्वारा की जाने वाली लूट कितनी ज्यादा है, इसका एक अंदाज तो इस बात से लगता है कि फरीदाबाद का तहसीलदार रोज़ाना दस लाख रुपये लेकर उठता है। इधर, तहसीलदार कहते हैं कि उन्हें हर जगह बेगार करनी पड़ती है। मंत्री आये अथवा कोई बड़ा अफ़सर, हर जगह 'सेवा-पानी' का बोझ उनके सिर पर ही रहता है।

एक बात और है। चूंकि इस विभाग में लूट की पूरी प्रक्रिया से मंत्री जी बेहतर परिचित हैं, इसलिए कहीं उन्होंने अधिकारियों का निलंबन कर यह संदेश देने की कोशिश तो नहीं की है कि भैया, हमारा हिस्सा भी सुरक्षित रखना और टाइम से उसे हमें पहुंचा देना। औचक निरीक्षण का मतलब होता है कि अधिकारी सुधर जायें और ग़लत काम करना छोड़ दें। पर एक दूसरा मतलब यह भी होता है कि हम भी आ गये हैं और हमारा हिस्सा बाकायदा तैयार रहना चाहिए। अब तो यह आने वाला समय ही बतायेगा कि मंत्री जी ने जो छापेमारी की, उसका निहितार्थ क्या था?

# फ़ोगाट को हरियाणा शिक्षा रत्न सम्मान

**फरीदाबाद (वि)** इरोज आईएमटी का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर सत्यपाल फ़ोगाट का नाम वर्ष 2008-2009 के 'हरियाणा शिक्षा रत्न' पुरस्कार के लिए घोषित किया गया। नगर के भिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने प्रो. फ़ोगाट को हारों से लाद दिया।

इरोज़ आईएमटी के एमडी मौसम तनेजा ने बताया कि आज़ादी के बाद फ़रीदाबाद की स्थापना से जुड़े, शिक्षक स्वर्गीय विशन तनेजा मैमोरियल संस्थान ने वर्ष 2008-09 में हरियाणा भर से प्राप्त 27 प्रविष्टियों में से श्री सतपाल फ़ोगाट का नाम चुना गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल डॉयरेक्टर ओपी तनेजा ने प्रो. सतपाल फ़ोगाट को एक रोल मॉडल बताया और कहा कि अपने शिक्षाधर्म, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और समाज के प्रति संपूर्ण समर्पण के कारण श्री फ़ोगाट एक लंबे अर्से तक एक उदाहरण के तौर पर चर्चित रहेंगे।

इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए राष्ट्रीय बुद्धिजीवी संस्थान के चेयरमैन ज्योतिसंग ने यह पंक्तियां पढ़ीं।

अपने कर्मों से कमाया, तूने अद्भुत नाम है।

तुझ को तेरे नाम को फ़ोगाट सौ प्रणाम हैं।

डीएवी संस्थान के प्रिंसिपल डॉ. सतीश अहूजा ने प्रो. फ़ोगाट को एक मील के पत्थर की संज्ञा देते हुए कहा कि आपको सम्मान देने से शिक्षा जगत स्वयं को सम्मानित महसूस करके गर्व का अनुभव कर रहा है। इस अवसर पर संस्थान की तरफ से यह घोषणा की गई कि स्वर्गीय श्री विशनदास तनेजा मेमोरियल संस्थान हर वर्ष हरियाणा के किसी एक शिक्षक अथवा शिक्षाविद को यह सम्मान प्रदान करेगा। देश के वरिष्ठ शिक्षाविदों का एक मंडल समस्त प्राप्त प्रविष्टियों का अध्ययन करके एक शिक्षक का चुनाव करेगा।

> "सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रो. सतपाल फ़ोगाट को एक रोल मॉडल बताया और कहा कि अपने शिक्षाधर्म, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और समाज के प्रति संपूर्ण समर्पण के कारण श्री फ़ोगाट एक लंबे अर्से तक एक उदाहरण के तौर पर चर्चित रहेंगे।"

डीएवी संस्थान को प्रोफेसर फ़ोगाट, शुभ तनेजा ने श्री फ़ोगाट को संतुलित प्रतिभा का व्यक्तित्व कहकर सम्बोधित किया और कहा कि ऐसे चंद व्यक्ति ही समय और काल की दिशा परिवर्तन की क्षमता रखते हैं।

इस अवसर पर प्रिंसिपल उदयवीर सिंह, डॉ. कड़वल, प्रिंसिपल जयवीर, प्रो. जेएस राना, नरेश राठी, अमरनाथ बागी, एमएस रजनीकर, डॉ. एके शरणा, जीपी गांधी, कैप्टन वीरेन्द्र सिंह और संपत कुमार नायडू ने भाग लिया। इसके अलावा डॉ. जसवंत सिंह, गुलशन बग्गा, पूर्व प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, ऋषिपाल चौहान, निदेशक जीवा स्कूल, पवन सूद, प्रसिद्ध रंगकर्मी, श्री रमन चदोतरा, रंगकर्मी, बलदेवराम शांत संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने प्रो. फ़ोगाट को बधाइयों से लाद दिया।

# विदेशी विश्वविद्यालयों का फैलता धंधा

बिड़ला-अंबानी रिपोर्ट को अमल में लाते हुए सरकार ने शिक्षा में निजी पूंजी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह डीम्ड विश्वविद्यालयों का तांता लगा दिया, उसी तरह विदेशी पूंजी को रिझाने के लिए वह विदेशी विश्वविद्यालयों को भी न्योता दे रही है। आज भारत में डेढ़ सौ विदेशी विश्वविद्यालय अपना धंधा चला रहे हैं। इनमें से इंगलैंड के 50, आस्ट्रेलिया के 45, अमेरिका के 30 और शेष कनाडा एवं अन्य यूरोपीय देशों के हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में किसिम-किसिम के लगभग 150 पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इनमें कुल 15000 विद्यार्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारत में धंधा कर रहे अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालय घटिया दर्जे के हैं। अपने देश में ही इनकी कोई साख नहीं है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित 150 पाठ्यक्रमों में से 44 को इनके देश में भी मान्यता नहीं है।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित करने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे भारत में विदेशी पूंजी आयेगी, नये-नये कैंपस बनेंगे और भारत में शिक्षा की कमी पूरी हो सकेगी। लेकिन जिस तरह अन्य क्षेत्रों में विदेशी पूंजी से उद्धार का गुब्बारा फिस्स हो गया, वैसा ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में एक चवन्नी भी खर्च नहीं किया है। इस बारे में प्रसिद्ध शिक्षाविद् आनन्द कृष्णन का कहना एकदम सही है कि शिक्षा में विदेशी पूंजीनिवेश एक मृगमरीचिका है।

विदेशी विश्वविद्यालय भारत में 'ट्विनिंग प्रोग्राम' चलाते हैं जिसके तहत आधी पढ़ाई भारत में और आधी पढ़ाई विदेश में होती है। इसके लिए वे भारत के किसी विश्वविद्यालय से गठजोड़ करके उनके कैंपसों का उपयोग करते हैं। कहावत है - जैसे को तैसा मिले, मिले चोर को चोर। उन घटिया दर्जे के विश्वविद्यालयों के साथ घटिया दर्जे के भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान ही साझेदारी करते हैं। वे बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगा कर और अख़बारों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन छपवा कर अपना प्रचार करते हैं और विश्वविख्यात होने का दावा करते हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की निगरानी या नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी गुणवत्ता की कोई जांच-परख या गारंटी न होने के बावजूद विदेशी डिग्री के नाम पर ऊंची फीस वसूलते हैं और अपना कूड़ा-कचरा भारत में उड़ेल देते हैं। भारत का नवधनाढ्य तबका उसे 'विदेशी डिग्री' के नाम पर लपक लेता है।

जहां तक विदेशों के नामी-गिरामी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की बात है, उनकी रुचि शिक्षकों की अदला-बदली तथा शोध और विकास जैसी गतिविधियों में ही होती है। इसके ज़रिये वे भारत के संसाधनों का प्रयोग कर अपने शोध कार्य को सस्ते में निपटा लेते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों का भारतीय छात्रों और शिक्षकों से कोई सरोकार नहीं। थोड़ा भी घाटे की संभावना हो तो वे बोरिया-बिस्तर समेट कर मुनाफ़े की तलाश में कहीं और चल देते हैं और छात्रों का भविष्य अधर में लटका रह जाता है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाला अमेरिकी संस्थान सेल्वन इंस्टीट्यूट घाटा होता देख प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ कर भाग गया। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय और इलीनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। भारत में बहुत से शिक्षा संस्थान धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा चलायें जाते हैं जिनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। अब व्यापार और सेवाओं के लिए आम सहमति (गैट्स) के तहत विदेशी संस्थान भी टैक्स में छूट और अन्य सभी सुविधायें हासिल करेंगे। विदेशी डिग्री बेचने वाली संस्थाओं ने ऐसी छूट हासिल कर ली है और भरपूर मुनाफ़ा बटोर रही है। बिड़ला-अंबानी रिपोर्ट को लागू करते हुए सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को छूट दी है कि वे किसी भी देशी नियम-कानून का पालन करने को बाध्य नहीं होंगे। इस तरह वे किसी भी प्रकार की वचनबद्धता या जिम्मेदारी से पूरी तरह आजाद हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में अपना कारोबार फैलाने का मकसद समझना कठिन नहीं है। इसके लिए कुछ तथ्य ही काफ़ी होंगे। फिनिक्स यूनिवर्सिटी दुनिया भर में एक व्यावसायिक संस्था की तरह शिक्षा का व्यापार करती है। यह कंपनी न्यू यार्क के शेयर बाज़ार में में सूचीबद्ध है और सट्टेबाज़ी में लिप्त है। शिक्षा क्षेत्र में एक अन्य विराट कंपनी है ग्लोबल एलायंस फॉर ट्रान्सनेशनल एजुकेशन, जो ऐसा ही धंधा करती है। नीट 'एनआईआईटी' और माइक्रोसॉफ़्ट भी कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया भर में जाल फैलाये हुए हैं। ये तथ्य इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत-प्रेम मुनाफ़े की हवस से पैदा हुआ है। ये भारत में शिक्षा का संकट दूर करने नहीं, बल्कि पूंजी-विस्तार का अपना संकट हल करने आये हैं।